



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032025-261718
CG-DL-E-19032025-261718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/ फाल्गुन 27, 1946

No. 79]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/ PHALGUNA 27, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर) – 01/2025

विषय : सऊदी अरब के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत - के संबंध में।

- i. फा. सं. 7/03/2025-डीजीटीआर – समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' कहा गया है) के अनुसार, मेसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' कहा गया है) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएई (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोल (जिसे इसके बाद 'एफएसपी' अथवा 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटन रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही वापस न ले लिया जाए, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांच की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी ने 11 जनवरी 2014 की अधिसूचना फ. सं 14/01/2013-डीजीएडी के तहत सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से एफएसपी के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जिसे अधिसूचना संख्या 9/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 7 अप्रैल 2015 के माध्यम से प्रभावी किया गया था। इसके बाद, सिंगापुर से आयात पर एक निर्णायक समीक्षा आयोजित की गई और प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं 7/12/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17 मार्च 2020 के माध्यम से अपने अंतिम निष्कर्ष जारी किए। निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14/2020- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जून 2020 के माध्यम से प्रभावी किए गए थे। पाटन रोधी शुल्क 8 जून 2025 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा गया था।
4. सऊदी अरब और यूएई से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच, दिनांक 18 दिसंबर 2019 की अधिसूचना फा.सं. 6/20/2019- डीजीटीआर के तहत शुरू की गई थी। अंतिम जांच परिणाम 1 सितंबर 2020 को जारी किए गए थे, जिनमें पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। जांच परिणामों को दिनांक 5 अप्रैल 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत प्रभावी किया गया था।
5. इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि सिंगापुर के संबंध में समीक्षा आरंभ करने का अनुरोध करने वाला आवेदन व्यापार नोटिस सं 02/2017 दिनांक 12 दिसंबर 2017 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात उत्पादक नहीं हैं जो भारत में उत्पाद का निर्यात कर सकें। इस प्रकार, इस समीक्षा जांच के उद्देश्य से सिंगापुर और यूएई को विषय देश नहीं माना जा रहा है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में परिभाषित उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है:

"ix. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोलेन है। संबद्ध उत्पाद 3000-4000 मोलिक्यूलर भार का एक स्पष्ट चिपचिपा लिक्विड पॉलिमर होता है, जिसे ट्रायोल चैन स्टार्टर के साथ प्रोपाइलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड का पॉलिमर करके निर्मित किया जाता है। यह एक पॉलीइथर है और केटेलेस्ट और एडिटिव के साथ प्रतिक्रिया करने पर पॉलियूरेथेन फोम उत्पन्न करता है जिसका उपयोग अपहोल्स्ट्री, मेट्रेस, तकिए, बोल्स्टर, ट्रांसपोर्ट सीटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है। फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोलेन को टैंकरों में ले जाया जाता है अथवा स्टील के ड्रमों में संग्रहीत किया जाता है (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" कहा गया है)।

x. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में "प्लास्टिक और तत्संबंधी वस्तुओं" की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 3907 20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अलग-अलग आईटीसीएचएस उद्धृत किए जा सकते हैं, लेकिन उत्पाद विवरण आईटीसीएचएस पर प्राथमिक माना गया है क्योंकि यह सांकेतिक है।"

7. चूंकि वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहा है जैसा कि मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।
8. संबद्ध वस्तुओं को दिनांक 1 फरवरी 2022 से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 अर्थात् "प्लास्टिक और तत्संबंधी वस्तुएं" के अंतर्गत शीर्ष 3907 और टैरिफ मद 3907 29 10 और 3907 29 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया

गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को आंशिक क्षति अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक के लिए उप शीर्ष 3907 20 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदक ने इस अवस्था में किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

10. आवेदक ने यह कहा है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (केओएच) प्रौद्योगिकी और डबल मेटल साइनाइड (डीएमसी) केटेलिस्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जा सकता है। आवेदक ने केओएच प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इस उत्पाद का उत्पादन किया है, जबकि संबद्ध देशों में निर्यातक दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादों का उत्पादन करते हैं। तथापि, आवेदक ने यह दावा किया है कि दोनों में से किसी भी उत्पादन प्रक्रिया से उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, अनुप्रयोगों और अंतिम उपयोगों, कीमतों आदि सहित सभी भौतिक पहलुओं में तुलनीय हैं। ग्राहक उत्पादों को अदल बदल कर उपयोग में लाते हैं।
11. तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात भौतिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रतिस्थापन करने योग्य है। अतः वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" मानी गई है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

12. नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग इस प्रकार है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा।"

13. यह आवेदन मेसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं है।
14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक के पास संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

15. वर्तमान समीक्षा जांच के उद्देश्य के लिए विषय देश सऊदी अरब है।

च. जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 माह) है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

छ. पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**i. सामान्य मूल्य**

17. आवेदक ने यह दावा किया है कि उसके पास सऊदी अरब में उत्पादकों के उत्पादन की वास्तविक लागत के संबंध में घरेलू बिक्री कीमत अथवा सूचना का कोई साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार, आवेदक ने अपने उत्पादन की लागत के आधार पर भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर एक सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें उचित लाभों को शामिल किया गया है। वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

ii. निर्यात कीमत

18. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात मूल्य डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, स्वदेशी माल भाड़ा और बैंक शुल्क के संबंध में कीमत समायोजन किया गया है ताकि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत प्राप्त की जा सके। संबद्ध देश के लिए दावा की गई निर्यात कीमतों के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

iii. पाटन मार्जिन

19. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। तथापि, चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः प्राधिकारी को यह जांच करनी आवश्यक है कि क्या मौजूदा शुल्कों को समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

20. आवेदक ने यह स्थापित करते हुए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रदान किया है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संदर्भ में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में काफी गिरावट आई है तथा संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है तथा उन पर दबाव डाल रहे हैं और कीमतों में कमी कर रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है तथा घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्रियों की लागत से भी कम है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप इसके बाजार अंश में भी गिरावट आई है। इसके चलते वस्तुसूचियों में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि पाटित किए गए आयातों की मौजूदगी के चलते काफी वित्तीय हानि, नकदी हानि और निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है।
21. इसके अलावा, आवेदक ने यह दावा किया है कि यदि शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश में निर्यातकों ने संबद्ध वस्तुओं का पाटन करना जारी रखा है, जिससे संबद्ध आयातों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है जबकि पहुंच कीमत में लगातार गिरावट आ रही है, संबद्ध आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर और अधिक भी निराशाजनक प्रभाव पड़ेगा।
22. सऊदी अरब के संबंध में पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मौजूद हैं।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

23. आवेदक के विधिवत रूप से प्रमाणित किए गए आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया साक्ष्य* के आधार पर, जो पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को प्रमाणित करता है तथा नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लगाए गए शुल्कों को जारी रखे जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने

और यह जांच करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं। कि क्या ऐसे शुल्कों के समाप्त होने से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज. प्रक्रिया

24. निर्णायक समीक्षा जांच में, दिनांक 1 सितंबर 2020 की अधिसूचना फा. सं. 6/20/2019- डीजीटीआर के तहत प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई है।
25. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

26. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों।
27. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिन्हें संबद्ध वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाना जाता है, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित फार्म और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।
28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के संबंध में अपने अनुरोध नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित फार्म एवं तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।
29. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
30. हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

31. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर भेजी जानी चाहिए, साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जब घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर अपने पश्चावली के उत्तर दाखिल करें।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

33. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी

संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन न करने पर प्रतिक्रिया/अनुरोध अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

34. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रस्तुत किए गए कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
35. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, तथा/ अथवा अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वह गोपनीय प्रकृति की है, अथवा ऐसी सूचना जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता होने का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण बताना भी आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित अथवा रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जिस पर गोपनीय होने का दावा किया गया है।
37. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश करने योग्य नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस तरह का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है, इसके कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
38. हितबद्ध पक्षकार अनुरोध के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाये की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
39. गोपनीयता के दावे पर नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और पर्याप्त कारण कथन के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
40. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत करने अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।
41. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर तथा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेगा।

६. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, और साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध के गोपनीय पाठ को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों के गोपनीय पाठ को प्रसारित न करने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

७. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त समय अवधि के भीतर अथवा प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2025

Case No. AD (SSR) - 01/2025

Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty concerning imports of "Flexible Slabstock Polyol" originating in or exported from Saudi Arabia - reg.

1. **F. No. 7/03/2025-DGTR** – An application has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), for initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred to as 'FSP' or 'subject goods' or 'product under consideration'), originating in or exported from Saudi Arabia, Singapore and UAE (hereinafter referred to as the 'subject country').
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATION

3. The Authority had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of FSP from Singapore, Australia and European Union vide Notification F. No. 14/01/2013-DGAD, dated 11th January 2014 which were given effect through Notification No. 9/2015-Customs (ADD) dated 7th April 2015. Thereafter, a sunset-review was conducted on imports from Singapore and the Authority issued its final findings vide Notification F. No. 7/12/2019-DGTR, dated 17th March 2020. The findings were given effect through Notification No. 14/2020- Customs (ADD), dated 9th June 2020. The anti-dumping duties were continued for the period of 5 years ending on 8th June 2025.
4. The anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from Saudi Arabia and UAE was also initiated vide Notification F. No. 6/20/2019-DGTR, dated 18th December 2019. The final finding was issued on 1st September 2020, recommending imposition of anti-dumping duty. The findings were given effect vide Customs Notification No. 20/2021-Customs (ADD), dated 5th April 2021.
5. In this regard, it is noted that the application requesting initiation of review with respect to Singapore was not filed within the timeline prescribed under the Trade Notice No. 02/2017 dated 12th December 2017. Additionally, it is noted that there are no known producers of the product under consideration in UAE which can export the product into India. Thus, Singapore and UAE are not being considered as subject countries for the purpose of this review investigation.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

6. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the final findings of the original investigation, which is as follows:

"ix. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol. The subject product is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter referred to as the "subject goods")."

x. The subject goods are classified under the category "Plastics and articles thereof" in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907 20 as per Indian Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority notes that while different ITCHS may be quoted by producers/exporters, the product description assumes primary over the ITCHS as the same is indicative."

7. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.
8. The subject goods are classified under Chapter 39 viz., "Plastics and articles thereof", of the Customs Tariff Act under heading 3907 and tariff item 3907 29 10 and 3907 29 90, with effect from 1st February 2022. Additionally, the product

has also been imported under the sub-heading 3907 20 for part of the injury period, i.e., 1st April 2021 to 31st January 2022. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

9. The applicant has not proposed any PCN at this stage. The parties to the present investigation may provide their comments, on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

C. LIKE ARTICLE

10. The applicant has claimed that the products produced by it are comparable in all material aspects, including the physical and chemical properties, applications and end uses, prices, etc. with the product under consideration imported from the subject countries. The customers use the products interchangeably.
11. Accordingly, it is noted that there are no known material differences in the article produced by the domestic industry and the product under consideration exported from the subject country. The article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The article manufactured by the domestic industry are technically and commercially substitutable with the product under consideration imported from the subject country. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the article produced by the domestic industry has been considered as “like article” to the product under consideration being imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"Domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry."

13. The application has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited. The applicant is the sole producer of the like article in India. The applicant has submitted that it is not related to any exporters of the subject goods from the subject countries or importer of subject goods in India.
14. The Authority notes that the applicant accounts for 100% of the total Indian production of the subject goods. In view of the same, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. SUBJECT COUNTRY

15. The subject country for the purpose of the present review investigation is Saudi Arabia.

F. PERIOD OF INVESTIGATION

16. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024 (12 months). The injury investigation period will cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the period of investigation.

G. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

i. Normal value

17. The applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price or information regarding actual cost of production of the producers in Saudi Arabia. Thus, the applicant calculated a normal value based on the price payable in India based on its own cost of production, with a reasonable addition of profits. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered the normal value as determined by the applicant.

ii. Export price

18. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of the subject goods based on the DGCI&S import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of export prices claimed for the subject country.

iii. Dumping margin

19. The normal value and export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above *de-minimis* level and is significant in respect of product under consideration from the subject country. However, since the present investigation is a sunset review, the Authority is required to examine whether cessation of existing duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

20. The applicant has provided *prima facie* evidence establishing that the subject imports have caused injury to the domestic industry. The volume of imports has increased significantly over the injury period both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The price of the imports from the subject countries has declined significantly and the subject imports are undercutting and are suppressing and depressing the prices of the domestic industry. Further, the subject imports are priced below the cost of the domestic industry and even lower than the raw material cost of the domestic industry. The production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry declined over the period, as a result of which its market share also declined. This has resulted in significant piling up of inventories. The domestic industry has claimed that the presence of dumped imports has resulted in significant financial losses, cash losses and negative return on investments.
21. Further, the applicant has claimed that there is likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry if the duties are allowed to expire. In this regard, the applicant has submitted that the exporters in subject country have continued to dump the subject goods, the volume of subject imports has increased continuously while the landed price has continued to decline, the subject imports are undercutting the domestic prices and would have further depressing effect on the prices of the domestic industry.
22. There is *prima facie* evidence regarding the likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty in respect of Saudi Arabia.

I. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

24. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification F. No. 6/20/2019-DGTR, dated 1st September 2020, recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
25. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be *mutatis mutandis* applicable in this review

K. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All communication should be sent to the Designated Authority *via* email at the email addresses <dir13-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
27. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
28. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.
29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
30. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. TIME LIMIT

31. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority *via* email at the email <dir13-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in> within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by or on behalf of the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (*including the nature of interest*) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

33. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.
34. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (*where indexation is not possible*) and such information must be appropriately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission.
39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTRs website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

O. NON-COOPERATION

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority